

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2320
04.08.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का प्रभाव

2320. श्री पी.पी.चौधरी :

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत :
श्री दिलीप शङ्कीया
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री गोडम नागेश :
श्री मनोज तिवारी :
श्रीमती कमलजीत सहरावत :
श्री कंवर सिंह तंवर :
डॉ. मन्ना लाल रावत :
श्री दामोदर अग्रवाल :
श्री बलभद्र माझी :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में वायु गुणवत्ता में सुधार पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का राजस्थान, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य-वार क्या प्रभाव है;
- (ख) क्या सरकार की मौजूदा 130 शहरों से आगे विस्तार करने की योजना है और यदि हां, तो कितने अतिरिक्त शहरों को शामिल करने का प्रस्ताव है और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
- (ग) क्या एनसीएपी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार लाने पर केंद्रित कोई विशिष्ट योजना या घटक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है; और
- (घ) महाराष्ट्र राज्य, विशेषकर मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की स्थिति क्या है?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा जनवरी 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का लक्ष्य महाराष्ट्र, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दस लाख से अधिक आबादी वाले और मानकों को पूरा नहीं करने वाले 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम में वर्ष 2014-2019 के दौरान लगातार 5 वर्ष की अवधि में पीएम10 के स्तरों के संबंध में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) से अधिक उत्सर्जन करने वाले शहरों के आधार पर मानकों को पूरा न करने वाले शहरों को शामिल किया गया है।

एनसीएपी के तहत 130 शहरों द्वारा की गई संकेंद्रित कार्रवाइयों के फलस्वरूप, 103 शहरों में वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम₁₀ की सांद्रता में कमी सहित सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कुल 22 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता संबंधी मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है और उनमें पीएम₁₀ की सांद्रता 60 µg/m³ से कम है। एनसीएपी के तहत शामिल किए गए शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार संबंधी ब्यौरा **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

06 शहर (दिल्ली, अलवर, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीआर) का भाग हैं और इन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्तपोषित किया जाता है। एनसीएपी के तहत शहरों द्वारा किए गए उपायों में राज्य और शहरी कार्य योजना तैयार करना, धूल नियंत्रण के लिए सड़क सुधार संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन, जैसे कि शुरु से अंत तक पक्की सड़कें बनाना, सड़कों की यांत्रिक सफाई करना, खुले स्थानों और यातायात गलियारों को हरा-भरा बनाना, भीड़भाड़ कम करने के लिए चौराहों पर यातायात में सुधार करना, शवदाहगृहों को स्वच्छतर ईंधनों में परिवर्तित करना या परंपरागत शवदाहगृहों में प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण संस्थापित करना, 'मेरा भारत' मंच के माध्यम से युवाओं को शामिल करके जन संपर्क और जागरूकता अभियान चलाना शामिल हैं। दिल्ली-एनसीआर के सभी 06 शहरों में वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम₁₀ की सांद्रता में सुधार देखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एनसीएपी के तहत दिल्ली को 62.03 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसमें से अब तक 13.94 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य के 19 शहरों को संबंधित शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार संबंधी उपाय करने के लिए एनसीएपी के तहत शामिल किया गया है। शहरी कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र को अब तक 1,774.62 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा सड़कों को शुरु से अंत तक पक्का बनाने, पुराने अपशिष्ट के शोधन, सार्वजनिक परिवहन के लिए ईवी बसें खरीदने, चौरहे पर यातायात में सुधार करने और शवदाहगृह को स्वच्छतर ईंधन में परिवर्तित करने जैसी संकेंद्रित कार्रवाइयों के फलस्वरूप 19 में से 15 शहरों में वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम₁₀ के स्तरों में सुधार देखा गया है। एनसीएपी के तहत मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों सहित महाराष्ट्र के शहरों को प्रदान की गई निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पीएम₁₀ की वार्षिक औसत सांद्रता

राज्य	क्र.सं.	शहर	प्रकार	वित्तीय वर्ष 2017-2018	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2024-25 में % सुधार
आंध्र प्रदेश	1	अनंतपुर	एनएसी	78	60	23.1
	2	चित्तूर	एनएसी	70	60	14.3
	3	एलुरु	एनएसी	72	64	11.1
	4	गुंटूर	एनएसी	66	64	3.0
	5	कडपा	एनएसी	75	56	25.3
	6	कुरनूल	एनएसी	79	60	24.1
	7	नेल्लोर	एनएसी	64	51	20.3
	8	ओंगोल	एनएसी	65	58	10.8
	9	राजामुंदरी	एनएसी	85	59	30.6
	10	श्रीकाकुलम	एनएसी	69	79	-14.5
	11	विजयवाड़ा	एमपीसी	91	64	29.7
	12	विशाखापत्तनम	एमपीसी	76	101	-32.9
	13	विजयनगरम	एनएसी	72	74	-2.8
असम	14	गुवाहाटी	एनएसी	103	100	2.9
	15	नगांव	एनएसी	82	65	20.7
	16	नलबाड़ी	एनएसी	87	85	2.3
	17	सिल्चर	एनएसी	49	54	-10.2
	18	शिवसागर	एनएसी	73	55	24.7
बिहार	19	पटना	एमपीसी	172	167	2.9
	20	गया	एनएसी	79	87	-10.1
	21	मुजफ्फरपुर	एनएसी	147	131	10.9
चंडीगढ़	22	चंडीगढ़	एनएसी	114	114	0.0
छत्तीसगढ़	23	कोरबा	एनएसी	57	69	-21.1
	24	दुर्ग भिलाईनगर	एमपीसी	86	69	19.8
	25	रायपुर	एमपीसी	70	75	-7.1
दिल्ली	26	दिल्ली	एनएसी	241	203	15.8
गुजरात	27	अहमदाबाद	एमपीसी	164	103	37.2
	28	राजकोट	एमपीसी	150	89	40.7
	29	सूरत	एमपीसी	130	71	45.4
	30	वडोदरा	एमपीसी	133	90	32.3
हरियाणा	31	फरीदाबाद	एमपीसी	229**	147	35.8
	32	बददी	एनएसी	174	108	37.9

हिमाचल प्रदेश	33	डमताल	एनएसी	55	56	-1.8
	34	काला अंब	एनएसी	118	84	28.8
	35	नालागढ़	एनएसी	146	68	53.4
	36	पोंटा साहिब	एनएसी	84	81	3.6
	37	परवाणू	एनएसी	66	48	27.3
	38	सुंदर नगर	एनएसी	78	47	39.7
जम्मू और कश्मीर	39	जम्मू	एनएसी	157	124	21.0
	40	श्रीनगर	एनएसी	132**	76	42.4
झारखंड	41	धनबाद	एमपीसी	315	166	47.3
	42	जमशेदपुर	एमपीसी	135	145	-7.4
	43	रांची	एमपीसी	141	107	24.1
कर्नाटक	44	बेंगलुरु	एमपीसी	92	68	26.1
	45	दावनगेरे	एनएसी	74	57	23.0
	46	गुलबर्गा/कलबुर्गी	एनएसी	55	52	5.5
	47	हुबली-धारवाड़	एनएसी	79	61	22.8
मध्य प्रदेश	48	भोपाल	एमपीसी	112	107	4.5
	49	देवास	एनएसी	83	86	-3.6
	50	ग्वालियर	एमपीसी	126	117	7.1
	51	इंदौर	एमपीसी	82	83	-1.2
	52	जबलपुर	एमपीसी	101	73	27.7
	53	सागर	एनएसी	73	79	-8.2
	54	उज्जैन	एनएसी	93	80	14.0
महाराष्ट्र	55	औरंगाबाद	एमपीसी	75	100	-33.3
	56	अकोला	एनएसी	111	74	33.3
	57	अमरावती	एनएसी	102	76	25.5
	58	बदलापुर	यूए	160	90	43.8
	59	चंद्रपुर	एनएसी	118	111	5.9
	60	ग्रेटर मुंबई	एमपीसी	161	90	44.1
	61	जलगांव	एनएसी	70	93	-32.9
	62	जालना	एनएसी	99	93	6.1
	63	कोल्हापुर	एनएसी	89	81	9.0
	64	लातूर	एनएसी	82	67	18.3
	65	नागपुर	एमपीसी	100	92	8.0
	66	नासिक	एमपीसी	82	76	7.3
	67	नवी मुंबई	यूए	88	90	-2.3
	68	पुणे	एमपीसी	102	93	8.8
	69	सांगली	एनएसी	87	74	14.9
	70	सोलापुर	एनएसी	81	83	-2.5
	71	ठाणे	यूए	138	90	34.8

	72	उल्हासनगर	यूए	153	90	41.2
	73	वसई विरार	एमपीसी	99	90	9.1
मेघालय	74	बर्नीहाट	एनएसी	175	98	44.0
नागालैंड	75	दीमापुर	एनएसी	142	112	21.1
	76	कोहिमा	एनएसी	127	71	44.1
ओडिशा	77	अंगुल	एनएसी	97	116	-19.6
	78	बालासोर	एनएसी	84	93	-10.7
	79	भुवनेश्वर	एनएसी	85	86	-1.2
	80	कटक	एनएसी	93	89	4.3
	81	कलिंग नगर	एनएसी	109	109	0.0
	82	राउरकेला	एनएसी	99	111	-12.1
	83	तालचेर	एनएसी	113	119	-5.3
पंजाब	84	अमृतसर	एमपीसी	189	112	40.7
	85	डेरा बाबा नानक	एनएसी	79	58	26.6
	86	डेरा बस्सी	एनएसी	88	98	-11.4
	87	जालंधर	एनएसी	178	99	44.4
	88	खन्ना	एनएसी	142	101	28.9
	89	लुधियाना	एमपीसी	168	129	23.2
	90	मंडी गोबिंदगढ़	एनएसी	148	124	16.2
	91	नया नंगल	एनएसी	87	58	33.3
	92	पटियाला	एनएसी	106	91	14.2
राजस्थान	93	जयपुर	एमपीसी	172	142	17.4
	94	अलवर	एनएसी	152	105	30.9
	95	जोधपुर	एमपीसी	189	122	35.4
	96	कोटा	एमपीसी	139	115	17.3
	97	उदयपुर	एनएसी	127	121	4.7
तमिलनाडु	98	चेन्नई	एमपीसी	66	58	12.1
	99	मदुरै	एमपीसी	72	61	15.3
	100	त्रिची	एमपीसी	88	57	35.2
	101	तूतीकोरिन	एनएसी	123	56	54.5
तेलंगाना	102	हैदराबाद	एमपीसी	110	81	26.4
	103	नलगोंडा	एनएसी	59	78	-32.2
	104	संगारेड्डी	एनएसी	85	86	-1.2
उत्तर प्रदेश	105	आगरा	एमपीसी	202	103	49.0
	106	इलाहाबाद	एमपीसी	169	99	41.4
	107	गाजियाबाद	एमपीसी	285	154	46.0
	108	कानपुर	एमपीसी	227	102	55.1
	109	लखनऊ	एमपीसी	253	142	43.9
	110	मेरठ	एमपीसी	159	133	16.4

	111	वाराणसी	एमपीसी	230	59	74.3
	112	अनपरा	एनएसी	175	155	11.4
	113	बरेली	एनएसी	207	48	76.8
	114	फिरोजाबाद	एनएसी	247	100	59.5
	115	गजरौला	एनएसी	204	148	27.5
	116	गोरखपुर	एनएसी	150	105	30.0
	117	झांसी	एनएसी	109	60	45.0
	118	खुर्जा	एनएसी	195	159	18.5
	119	मुरादाबाद	एनएसी	222	96	56.8
	120	नोएडा	एनएसी	229	149	34.9
	121	रायबरेली	एनएसी	145	79	45.5
उत्तराखंड	122	देहरादून	एनएसी	250	107	57.2
	123	काशीपुर	एनएसी	99	93	6.1
	124	ऋषिकेश	एनएसी	129	84	34.9
पश्चिम बंगाल	125	आसनसोल	एमपीसी	147	131	10.9
	126	बैरकपुर	यूए	86	92	-7.0
	127	दुर्गापुर	एनएसी	150	149	0.7
	128	हल्दिया	एनएसी	92	81	12.0
	129	हावड़ा	यूए	139	92	33.8
	130	कोलकाता	एमपीसी	147	92	37.4

टिप्पणी :

एमपीसी - दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (पंद्रहवें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान (मिलियन-प्लस सिटी चैलेंज फंड) के तहत वित्तपोषित शहर)

यूए - शहरी समूह (पंद्रहवें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान (मिलियन-प्लस सिटी चैलेंज फंड) के तहत वित्तपोषित शहर)

एनएसी - मानकों को पूरा न करने वाले शहर (सीपी स्कीम के तहत वित्तपोषित शहर)

** फरीदाबाद और श्रीनगर के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के पीएम₁₀ के स्तर उपलब्ध नहीं हैं। फरीदाबाद के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के पीएम₁₀ के स्तर और श्रीनगर के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के पीएम₁₀ के स्तर को आधाररेखा माना गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एनसीएपी के तहत महाराष्ट्र के शहरों को प्रदान की गई निधि का ब्यौरा

क्र.सं.	शहर/शहरी समूह	शहर का नाम	जारी की गई (करोड़ रुपये में)	उपयोग की गई (करोड़ रुपये में)
1	मुंबई यूए	ग्रेटर मुंबई	629.62	523.38
		कल्याण-डोम्बीवली	65.2	23.56
		मीरा-भायंदर	42.75	25.66
		अंबरनाथ	13.96	2.69
2		ठाणे	93.24	71
3		नवी मुंबई	68.2	60.4
4		उल्हासनगर	27.13	24.16
5		बदलापुर	12.04	8.86
6	महाराष्ट्र के अन्य शहर	पुणे	271.3	243.13
7		नासिक	91.55	75.54
8		औरंगाबाद	68.3	61.47
9		नागपुर	142.05	91.67
10		वसई विरार	72.35	71.39
11		अमरावती	36.81	32.83
12		कोल्हापुर	25.59	18.7
13		सांगली	12.93	9.44
14		सोलापुर	43.49	40.12
15		अकोला	10.71	9.5
16		चंद्रपुर	12.07	6.74
17		जलगांव	6.63	4.21
18		जालना	7.39	6.14
19		लातूर	21.33	17.37
कुल			1774.64	1427.96
